

# भारत का याजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—संख 3—उत्तराधि (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441] नई दिल्ली, वृद्धतिवार, अक्टूबर 5, 1972/ग्राहितन 13, 1894

No. 441] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 1972/ASVINA 13, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या थी जाती हैं जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

### MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

#### ORDER

New Delhi, the 5th October 1972

**S.O. 641(E)/18A/IDRA/72.**—Whereas the Central Government is of the opinion that Rampuria Cotton Mills Limited, Serampore, P.O. Rishra (District Hooghly), an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the following body of persons:—

*Chairman*

1. Shri A. Bose, Special Officer and *e.x-officio* Secretary to the Government of West Bengal, Department of Closed and Sick Industries, Calcutta

## Members

2. Shri S. C. Chakravarti, I.A.S. (Retired),
3. Shri M. M. Sanyal, Commercial Accountant, Directorate of Labour, West Bengal.

(hereinafter referred to as the authorised body of persons) to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, Rampooria Cotton Mills Limited, Serampore, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (i) the authorised body of persons shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;
- (ii) the authorised body of persons shall hold office for five years from the date of publication of this order in the Official Gazette;
- (iii) the Central Government may terminate the appointment of the authorised body of persons earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F. 3/37/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

श्रीद्वौगिक विकास मंत्रालय

(श्रीद्वौगिक विकास विभाग)

आदेश

दर्दि दिल्ली, 5 अक्टूबर, 1972

का० प्रा० 641(अ)/18ए/प्राई० डी० प्रा० ६०/७२.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि रामपुरिया काटन मिल्स लिमिटेड, सीरमपुर, डाकधर गिरा (जिला हुगली), श्रीद्वौगिक उपक्रम का जिसकी बाजत उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के प्रधीन प्रबन्धण किया जा चुका है, प्रबन्ध इस रिति में किया जा रहा है कि लोक हित में प्रति अहितकर है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 18क द्वारा प्रदत्त ग्रक्षितयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित व्यक्तियों,

1. श्री ए० बोम

अध्यक्ष

विषेष अधिकारी श्रीर पदेन मचिव

पश्चिम बंगाल सरकार, बन्द

श्रीर अव्यस्थित उद्योग विभाग, कलकत्ता ।

2. श्री ए० सी० चत्रवर्ती,

सदस्य

आई० ए० ए० (सेवा-निवृत)

3. श्री ए० ए० संयाल,

सदस्य

वाणिजिक लेखापाल, श्रम निदेशालय,

पश्चिम बंगाल ।

के निकाय को (जिसे इस में उसके पश्चात प्राधिकृत व्यक्तियों का निकाय कहा गया है) उक्त उपक्रम अर्थात् रामपुरिया काटन मिल्स लिमिटेड, सीरमपुर का पूर्ण प्रबन्ध निम्ननिवित नियन्त्रणों और शर्तों के अधीन रहते हुए, ग्रहण करने के लिए एन्ड्राका प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

- (i) प्राधिकृत व्यक्तियों का निकाय केन्द्रीय भरकार द्वारा ममय-ममय पर निकाले गए सभी निर्देशों का पालन करेगा ;
- (ii) प्राधिकृत व्यक्तियों का निकाय गजपत्र से हम आदेश के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष के लिए पदासीन रहेगा ;
- (iii) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकृत व्यक्तियों के निकाय को नियुक्ति, यदि वह ऐसा करता आवश्यक समझे तो, पहले ही समाप्त कर सकेगी ।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा ।

[सं० फा० 3/37/72-सी० य० सी०]  
के० ए० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

